भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ
Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh
(AN ALL INDIA FEDERATION OF DEFENCE WORKERS)
(AN INDUSTRIAL UNIT OF B.M.S.)
(RECOGNISED BY MINISTRY OF DEFENCE, GOVT. OF INDIA)

CENTRAL OFFICE : 2-A, NAVIN MARKET, KANPUR-1 • PH.: (0512) 2332222 • FAX : (0512) 2296229
Mob. : 09335621629, 09415726924, 09415733686 • E-mail : gensecbpms@yahoo.co.in, cecbpms@yahoo.in

REF: BPMS/ MoD/ Workload/ 186(8/1/R) Dated: 17.11.2022

To
Shri Rajnath Singh Ji,
Hon,ble Raksha Mantri Ji
Govt of India, Ministry of Defence
South Block, New Delhi – 110 011

बिषय:- नवगठित Defence PSU को संरक्षित करने के सम्बंध में।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि भारत सरकार के द्वारा 01 अक्टूबर 2021 से OFB को सात भागों में बांटते हुए सरकारी संस्थान के स्थान पर Defence PSU में परिवर्तित किया गया और कहा गया कि यह सातों PSU में सरकार का 100% स्वामित्व रहेगा, अर्थात यह PSU भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के उपक्रम के रूप में ही काम करेंगे। Cabinet Note में OFB के सभी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को भी protect करने का आश्वासन भी सरकार द्वारा दिया गया। ग्रुप A, B, C के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों को बतौर सरकारी कर्मचारी protect करते हुए इन नवनिर्मित DPSU में 2 साल के लिये Deemed Deputation पर रखा गया।

महोदय, कारपोरेशन से पूर्व मान्यता प्राप्त महासंघो के साथ लगातार अधिकारी स्तर की कई वार्ताएं सम्पन्न हुई। महासंघो ने लगातार इन वार्ताओं में आयुध निर्माणियों की स्थितियों से अवगत कराया कि यह निर्माणियां corporation में survive नहीं कर पायेगी क्योकि इन आयुध निर्माणियों का structure व्यापारिक संस्थानो से भिन्न है। Over-head बहुत अधिक होने से यह निर्माणियां निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पायेगी और work-load के अभाव में अपने वेतन भत्ते नहीं कमा पाएगी। OFB में सुधार हेतु महासंघों ने MoD को 2 proposal भी दिए थे जिनमें मांग की गयी थी कि सरकारी department के रूप में ही OFB में सुधार किए जाय। सरकार और Armed Forces की जो अपेक्षायें है उन्हें हम पूरी करके दिखाएंगे परन्तु महासंघों के विचारों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। सरकार ने एकतरफा निर्णय लेते हुए OFB को corporation करने का निर्णय ले लिया।

महोदय, महासंघों ने वार्ताओं के दौरान work-load की समस्याओं से भी अधिकारी पक्ष को अवगत कराया था कि आने वाले समय मे इन PSU के पास work-load की समस्या खड़ी होगी लेकिन उस समय अधिकारी पक्ष द्वारा यही आश्वासन दिया गया कि किसी भी PSU को work-load की कमी नही होने दी जाएगी।

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने लगभग सभी meetings के दौरान यह चेताया कि TCL (OFB के अंतर्गत OEF ग्रुप जिसे corporation के बाद TCL/ Troops Comfort Limited नाम दिया गया) में work-load कुछ ही सालों में उपलब्ध नहीं हो पाएगा क्योंकि इस group के अधिकांश उत्पाद non-core किये जा चुके हैं। महासंघ ने यह भी मांग की थी कि इन निर्माणियों के उत्पाद बदले जाए और कर्मचारियों को नए उत्पाद के अनुरूप आवश्यक training दी जाय। कुछ स्थानों पर training शुरू भी हुई परन्तु वह भी मात्र औपचारिकता बनकर रह गई।

जैसी इस महासंघ को आशंका थी वह सत्य सिद्ध हुई। वित्त वर्ष 2023-24 के लिये TCL के पास मात्र 89 करोड़ का लक्ष्य है जबकि वर्ष 2022-23 में लगभग 1100 करोड़ का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसके पूर्व के वर्षों में भी लगभग 1000 करोड़ का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त होता रहा है। 1100 करोड़ के स्थान पर 89 करोड़ से एक फैक्ट्री भी नहीं चल सकती। सरकारी विभाग होने के कारण अभी तक nomination के आधार पर उत्पादन लक्ष्य प्राप्त होता था। Corporation के बाद निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करना है इसलिये उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। आयुध निर्माणियां specification के आधार पर उच्च गुणवत्तापूर्ण material का उपयोग करती है जबकि निजी क्षेत्र अपने लाभ के लिये material की quality से समझौता करते है, कर्मचारियों के वेतन भत्ते प्रदान करने में भी निजी क्षेत्र शोषण करते है। निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा में उपरोक्त कारण भी आयुध निर्माणियों के लिए बाधा हैं।

TCL Group की निर्माणियां विभिन्न प्रकार की यूनिफार्म जैसे Army Logo, Combat Uniform, कम्बल, Coat Combat, Coat ECC, शर्ट अंगोला, सेना के काम में आने वाले विभिन्न प्रकार के Tent, जर्सी, Socks, विभिन्न प्रकार के Boots आदि का सफलता पूर्वक उत्पादन करती आ रही है।

महोदय New Combat Uniform Digital Print की आपूर्ति के लिये रक्षा मंत्रालय के Department of Military Affairs के द्वारा एक Bid GEM/2022/B/2579671 दिनांक 6 अक्टूबर 2022 प्रकाशित की गयी जिसमें ऐसी शर्ते रखी गई है जिससे TCL भाग ही नहीं ले सकता। इस Bid के बिंदु संख्या 19C में स्पष्ट किया गया है कि वो Firm / Company भाग ले सकती है जिसने पिछले तीन वर्षो में 2 वर्ष लाभ कमाया हो। TCL का निर्माण 1 अक्टूबर 2021 को हुआ, अभी 01 साल ही पूरा किया है इसलिये इस Bid में TCL सम्मिलित ही नहीं हो सकता। इस Bid के बिंदु संख्या 19D की शर्त के अनुसार वही Firm / Company इस Bid में सम्मलित हो सकेगी जिसके पास Wet Processing, Dyeing, Printing और Garmenting की क्षमता व मशीनरी हो। आयुध निर्माणियों के पास मात्र Garmenting की क्षमता व मशीनरी है। यह एक लंबे समय से Garmenting ही करती आ रही है। यह निर्माणियां निजी क्षेत्र की मिलों से कपड़ा खरीदकर Garmenting करती है। Wet Processing, Dyeing और Printing की व्यवस्था कपड़ा बनाने वाली Firm / Company के ही पास होती है। इसलिये TCL इस Bid में भाग नहीं ले सकती। वर्तमान समय में Army Logo Combat Uniform का कपड़ा निजी क्षेत्र से खरीदकर Uniform तैयार करती है, इस प्रकार 19c और 19d की शर्तों को पूरा न कर पाने के कारण टीसीएल स्वतः बाहर हो गई।

महोदय TCL एक नई Defence PSU है यदि इस समय इसको Protect न किया गया तो यह आयुध निर्माणियां बंद हो जाएगी और इन चार निर्माणियों में कार्यरत लगभग 6000 कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।

आपसे विनम्र निवेदन है कि Combat Uniform Digital Print की Garmenting का कार्य TCL को प्रदान किया जाय। साथ ही, TCL ग्रुप की निर्माणियो को भरपूर वर्कलोड अगले पाँच वर्ष के लिए

Nomination Basis पर दिया जाय, जिससे कि इस अवधि के दौरान ये अपनी व्यापारिक क्षमताओ का विकास कर सके।

साथ ही, इस गंभीर विषय पर बात करने व मुख्य बिन्दुओ पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का एक प्रतिनिधिमण्डल आपके बहुमूल्य समय से कुछ समय की मांग करता है। आपसे निवेदन है कि प्रतिनिधिमण्डल को समय प्रदान करने की कृपा करें।

Thanking you

Sincerely Yours

M.K Singh

(MUKESH SINGH)
General Secretary/ BPMS &
Member JCM II Level Council (MoD)

Copy to:

1. The The Defence Secretary
   South Block, New Delhi
2. The CMD /TCL
   G.T.Road, Kanpur

- For kind information and necessary action please.